भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1778
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों का संशोधन

1778. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कें, जिनमें नलगोन्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें भी शामिल हैं, को प्रायः 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट लेन तक ही सीमित रखा जाता है , जिससे गंभीर सड़क सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएँ बढ़ती हैं;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान नलगोन्डा लोक सभा क्षेत्र तथा देश भर में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित संकरी सड़कों के कारण हुई दोनों जानलेवा और गैर-जानलेवा दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का अधिक यातायात भार अथवा दुर्घटना-प्रवण ग्रामीण क्षेत्रों में दो-लेन (7 मीटर चौड़ी) सड़कों के निर्माण की अनुमति देने के लिए पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों में संशोधन का विचार है;

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई निर्धारित करने के लिए वर्तमान मापदंड क्या हैं;

(ङ) क्या सड़क की चौड़ाई निर्धारित करते समय यातायात घनत्व तथा दुर्घटना संबंधी आँकड़ों पर विचार किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सड़क सुरक्षा में सुधार , जिसमें मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण तथा संकेतक , प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुरक्षा सुविधाएँ शामिल है, के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशानिर्देशों , भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों और ग्रामीण सड़क संहिता के प्रावधानों के अनुसार , नलगोन्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों सहित सड़कों की कैरिजवे चौड़ाई , सड़कों पर प्रतिदिन चलने वाली यात्री कार इकाई (पीसीयू) के संदर्भ में अनुमानित यातायात , मौजूदा

कैरिजवे चौड़ाई, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर तय की जाती है। सड़क पर चलने वाले यातायात (पीसीयू/दिन) और अन्य जगह-विशिष्ट कारकों के आधार पर कैरिजवे को 3.75 मीटर या 5.5 मीटर तक चौड़ा किया जा सकता है , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजते समय आकलन और प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के तहत कार्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी जाती है और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

"ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ें नहीं रखता है। हालांकि, राज्य ने बताया है कि पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना ने सभी सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट (अत्यधिक-दुर्घटना आशंकित क्षेत्र) की पहचान की है और बताया है कि वर्तमान में नलगोन्डा में पीएमजीएसवाई सड़कों पर कोई ब्लैक-स्पॉट नहीं है।

(ग) से (ङ): पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी), ग्रामीण सड़क संहिता (आईआरसी-एसपी: 20) और आवश्यकतानुसार पहाड़ी सड़क संहिता (आईआरसी:एसपी:48) तथा अन्य प्रासंगिक आईआरसी कोड और संहिता में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है। इस योजना के तहत कार्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी जाती है और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। डीपीआर में पीसीयू मूल्यों के संदर्भ में यातायात की संख्या को ध्यान में रखा जाता है जो सड़क की चौड़ाई को अंतिम रूप देने में एक निर्णायक कारक है। आईआरसी में अनुशंसित लंबाई: एसपी: ग्रामीण सड़कों के लिए 20 मैनुअल 3.75 मीटर है और कम वक्रता वाले मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित आईआरसी एसपी 64 1990 मैनुअल निम्नलिखित पीसीयू मान हैं:

पीसीयू मूल्य	**अनुशंसित सड़क की चौड़ाई**
2,000 तक	3.75 मीटर
6,000 तक	5.5 मीटर (मध्यवर्ती)
15,000 तक	7.5 मीटर (डबल लेन)

(च): सड़क सुरक्षा एक बहु-विषयक गतिविधि है। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से , मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा एक ग्रामीण सड़क सुरक्षा नियमावली तैयार की गई है और सभी राज्य ग्रामीण सड़क

विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) को सुरक्षित ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए परिचालित की गई है। नियमावली में सुरक्षित सड़क डिजाइन , सड़क सुरक्षा अंकेक्षण जांच सूची , सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा पर मार्गदर्शन शामिल है। पीआईयू, परामर्शदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए सुझावात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी दिए गए हैं।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-।।। के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं , जिनका राज्यों को योजना के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय पालन करना आवश्यक है। डीपीआर तैयार करने के दौरान सुरक्षा पहलू सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होना चाहिए। 'ट्रांसेक्ट वॉक' चरण में ही , कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है ताकि खतरों, स्थानीय ब्लैक-स्पॉट्स और संभावित सुधार उपायों को चिन्हित किया जा सके।

इसके अलावा, राज्यों को सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में 5 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सभी पीएमजीएसवाई सड़कों के डिजाइन चरण की लेखा परीक्षा करना होगा। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि 5 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सभी ग्रामीण सड़कों , जिन पर अभी कार्य शुरू होना है या कार्य प्रगति पर है, की सुरक्षा के लिए लेखा परीक्षा की जाए। सुधारात्मक उपायों/रेट्रोफिटिंग करने के लिए संचालन में मौजूदा ग्रामीण सड़कों की भी लेखा परीक्षा/निरीक्षण किया जाना था। पीएमजीएसवाई-।V के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कें , सड़क संकेतों, फुटपाथ चिह्नों, क्रैश बैरियर, निर्माण क्षेत्रों में सुरक्षा आदि से संबंधित नियमावली के अनुपालन में होंगी।

****